ई संदेश

02 जुलाई, 2026 | अंक - 212

सात दिन, सात पृष्ठ

- लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना को मंजूरी 'विकसित कृषि रोडमैप-2047' पर केन्द्र व राज्य की संयुक्त समीक्षा
- विकास और विरासत को मिल रहा सम्मान; धनघटा और खजनी को मिली 475 करोड़ रुपये की सौगात
- डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड से उत्तर प्रदेश में हो रहा चहुंमुखी विकास: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत केंद्र बना गोरखपुर, मुख्यमंत्री ने किया फोर्टिस के सहयोग से निर्मित नए हॉस्पिटल का शुभारम्भ
- उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब मुख्यमंत्री ने किया जेवर में मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास
- जेवर में सौर ऊर्जा क्रांति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ₹8,200 करोड़ के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया शिलान्यास
- नोएडा में ₹2,479 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य प्रशासनिक भवन का लोकार्पण
- हाथरस बनेगा नया औद्योगिक और रोजगार का गढ़: मुख्यमंत्री
- पीलीभीत में सौर ऊर्जा, इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईको-टूरिज्म को मिली रफ़्तार
- पीतल नगरी में प्रगति की नई गूंज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को दी ₹365.50 करोड़ की सौगात
- स्मार्ट और स्वच्छ बरेली की ओर मजबूत कदम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को दिखाई हरी झंडी
- सहारनपुर में ₹613 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून कॉरिडोर से आर्थिक प्रगति को मिलेगी नई उड़ान
- मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से राज्यव्यापी 'स्कूल चलो अभियान'का शुभारम्भ किया , बच्चों को बांटी पाठ्य-सामग्री
- रामपुर में नए चैप्टर की हुई शुरुआत : मुख्यमंत्री ने किया ₹690 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना को मंजूरी 'विकसित कृषि रोडमैप-2047' पर केन्द्र व राज्य की संयुक्त समीक्षा

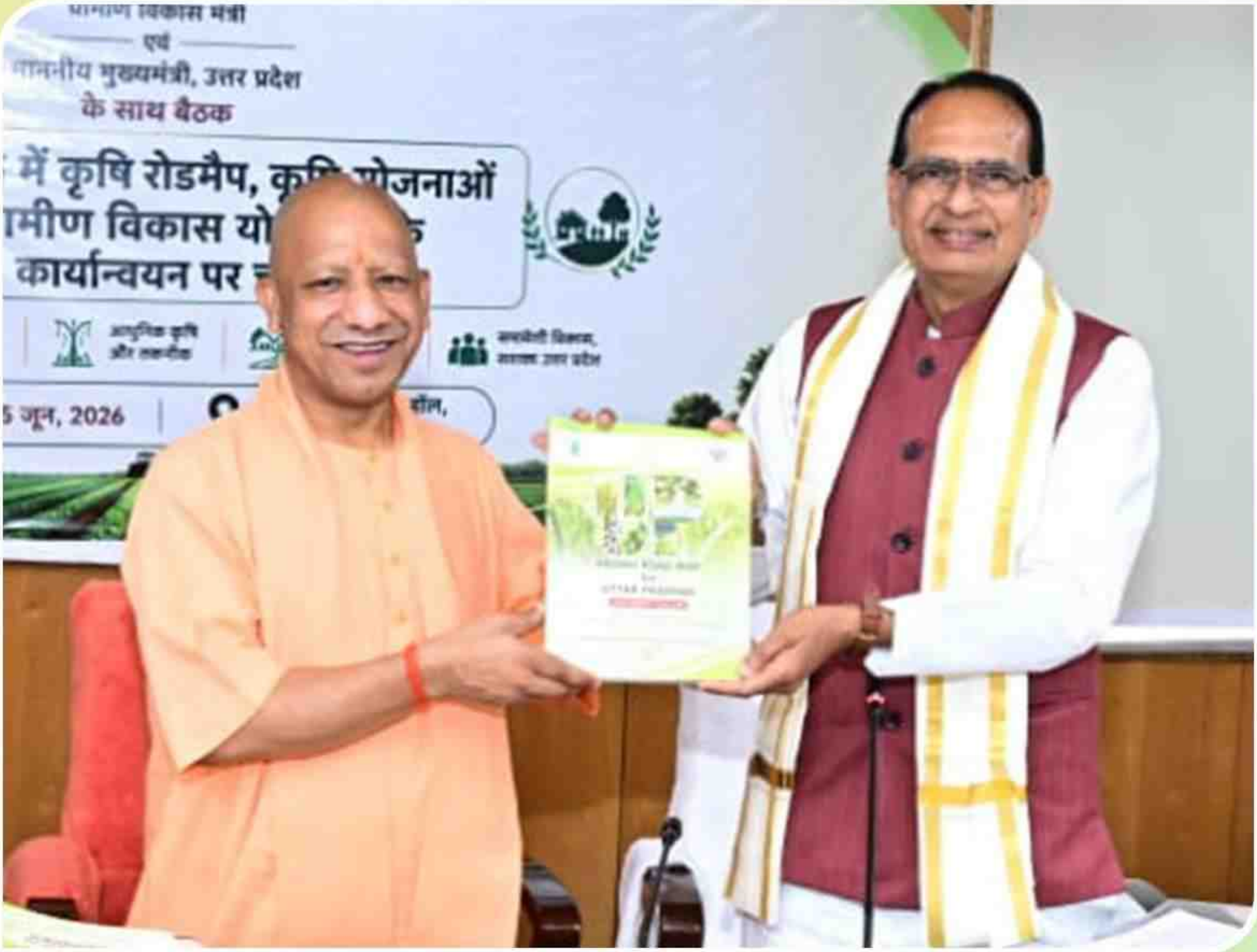

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 25 जून, 2026 को लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश के 'विकसित कृषि रोडमैप-2047', विभिन्न केन्द्रीय व राज्य कृषि योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की।

इस महत्वपूर्ण बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से लखनऊ में एक आधुनिक 'क्लीन प्लाण्ट सेन्टर' स्थापित करने की बड़ी घोषणा की। इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त एवं रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे औद्यानिकी क्षेत्र का विस्तार होगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत संकल्प' को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध और अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार ने आपसी समन्वय से आगे बढ़ने का साझा संकल्प लिया। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए इस सेंटर की स्वीकृति देने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आगामी चरण के लिए पात्र 6,18,482 नए लाभार्थियों की सूची सौंपने तथा चना, मसूर एवं सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने के लिए केन्द्रीय मंत्री के प्रति विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक, लाभकारी एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा तैयार 'विकसित कृषि/2047-उत्तर प्रदेश कार्ययोजना' राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को वर्तमान 7.41 ट्रिलियन रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 96.96 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए वास्तविक कृषि वृद्धि दर को 3.19 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.41 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक के दौरान आईसीएआर के महानिदेशक ने 'विकसित कृषि/2047-उत्तर प्रदेश कार्ययोजना' पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें धान और गेहूं पर निर्भरता कम करते हुए दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण तथा आधुनिक तकनीकों के विस्तार पर बल दिया गया। कार्ययोजना के तहत कृषि यंत्रीकरण को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने और हर जनपद में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तथा डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाने का खाका खींचा गया, जिससे किसानों की शुद्ध आय में 109 से 162 प्रतिशत तक की शानदार वृद्धि का अनुमान है।

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कृषि विविधीकरण, सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रभावी उपयोग, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए बैंकों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की उपलब्धता में केन्द्र की ओर से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

विकास और विरासत को मिल रहा सम्मान; धनघटा और खजनी को मिली 475 करोड़ रुपये की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 25 जून, 2026 को जनपद संतकबीर नगर के धनघटा तहसील स्थित प्राचीन शिव मंदिर बाबा बैजूनाथ धाम परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा एवं जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी के विकास के लिए 475 करोड़ रुपये लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रतीकात्मक चेक, प्रशस्ति-पत्र और टूल किट वितरित कर उन्हें स्वावलंबी बनने का उपहार दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने नन्हें बच्चों का पूरे स्नेह से अन्नप्राशन भी कराया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब जनता द्वारा जागरूक होकर अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रदेश में एक संवेदनशील व उत्तरदायी सरकार होती है, तो विकास और विरासत दोनों को समान रूप से सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि कभी उपेक्षित, पिछड़े और विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके धनघटा और खजनी क्षेत्र आज डबल इंजन सरकार के निरंतर प्रयासों से विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं में 225 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं धनघटा विधानसभा और 251 करोड़ रुपये की परियोजनाएं खजनी विधानसभा के चहुंमुखी विकास को समर्पित हैं, जिससे आने वाले समय में इन क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने सुशासन और सुरक्षा को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि एक अच्छी और लोक-कल्याणकारी सरकार के आने से ही समाज में सुरक्षा का उत्कृष्ट वातावरण बनता है। इसी सुरक्षित माहौल के कारण आज प्रदेश के हर गरीब को उसका वास्तविक अधिकार, अन्नदाता किसानों को सम्मान, हर खेत को पानी और नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का सबसे सशक्त 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभर रहा है। प्रदेश में हाईवे, एक्सप्रेस-वे, जनपदीय और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी को अत्यधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे गांवों और शहरों के बीच की दूरी कम हुई है और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है।

शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा देने के लिए रिकॉर्ड संख्या में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। 'ऑपरेशन कायाकल्प' और 'प्रोजेक्ट अलंकार' के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की सूरत बदली जा रही है, जबकि अटल आवासीय विद्यालयों व मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालयों के जरिए समाज के वंचित तबके के भावी पीढ़ी के भविष्य को संवारा जा रहा है। उन्होंने मगहर में संतकबीर एकेडमी और ऑडिटोरियम के निर्माण, गीडा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार तथा धुरियापार में 'ग्रेटर गीडा' की स्थापना का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन युगांतरकारी प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों-लाखों नौजवानों के लिए स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार की नई व असीम संभावनाएं पैदा हुई हैं, जिससे पलायन पर प्रभावी रोक लगी है।

मुख्यमंत्री जी ने आस्था के सम्मान और पर्यटन विकास की चर्चा करते हुए एक बड़ी घोषणा की कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को एक नई और भव्य पहचान देने के लिए इसे श्री काशी विश्वनाथ धाम और माँ विन्ध्यवासिनी धाम की तर्ज पर एक शानदार कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मेंहदावल की प्रसिद्ध बखिरा झील को रामसर साइट के रूप में ईको टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की सुगमता को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माध्यम से अब धनघटा और बेलघाट के नागरिकों के लिए राजधानी लखनऊ की दूरी मात्र दो घंटे में तय करना संभव हो गया है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।

संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जनता को खुशखबरी दी कि केन्द्र सरकार के साथ हुई हालिया समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के 6 लाख 18 हजार से अधिक गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध है।

डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड से उत्तर प्रदेश में हो रहा चहुंमुखी विकास: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 जून, 2026 को जनपद देवरिया के बरहज एवं रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। राज्य सरकार जनता की प्रत्येक अपेक्षा पर खरी उतर रही है और देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ तथा आजमगढ़ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में तीव्र गति से विकास हो रहा है। सभी क्षेत्रों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सड़क कनेक्टिविटी तथा विकासपरक योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, स्वीकृति पत्र, चाबियां तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके पूर्व, उन्होंने महिलाओं की गोदभराई, बच्चों का अन्नप्राशन कराया और वहां आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री जी ने देवरिया के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह जनपद महर्षि देवरहा बाबा की पावन साधना स्थली है और राघव बाबा ने इस क्षेत्र से देश की आजादी की अलख को आगे बढ़ाया था। डबल इंजन सरकार के माध्यम से जनपद में विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय दिखायी दे रहा है। विगत दिनों देवरिया में पत्थरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। पडरौना से कसया, पत्थरदेवा, सोनू घाट तथा बरहज होते हुए, दोहरी घाट व वाराणसी-गोरखपुर मार्ग से जोड़कर पूर्व-पश्चिम की बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। अब उत्तर-दक्षिण की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के तहत हाटा से गौरी बाजार तथा रुद्रपुर होते हुए कौड़ीराम तक सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे विकास जनता के द्वार तक पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी तथा अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। अच्छी रोड, रेल व्यवस्था, स्किल्ड मैन पावर, पर्याप्त लैंड बैंक और जल संसाधन की उपलब्धता उत्तर प्रदेश की खूबी है। दुनिया में सर्वाधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में है। इस युवा शक्ति के बल पर हम प्रदेश के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए युवाओं की स्किलिंग करते हुए उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। प्रदेश के 09 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में देवरिया के सैकड़ों युवा चयनित हुए हैं। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 03 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत युवाओं को 05 लाख रुपये का ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण और मार्जिन मनी दी जा रही है। इससे युवा विभिन्न कार्यों से जुड़कर आमदनी कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। राज्य की कृषि विकास दर 08 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई है और आज प्रदेश अनेक खाद्यान्नों में नंबर एक पर रहते हुए देश को लीड कर रहा है। सरकार ने जीरो टॉलरेन्स की नीति के अन्तर्गत सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण निर्मित किया है, जिससे बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुए हैं। अपराधियों और अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। सुरक्षा के परिणामस्वरूप देवरिया, गोरखपुर तथा कुशीनगर जैसे शहरों में निवेश हो रहा है और उद्यम लग रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने निवेश प्रक्रिया के साथ 65 लाख युवाओं को जोड़ा है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है। पिछली सरकार ने इसकी लागत 15,800 करोड़ रुपये तथा चौड़ाई 110 मीटर तय की थी, जबकि वर्तमान सरकार ने चौड़ाई बढ़ाकर 120 मीटर की और निर्माण मात्र 11,200 करोड़ रुपये में पूर्ण कराकर बड़ी बचत की। जनप्रतिनिधियों की मांग पर देवरिया के मोहन सेतु के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और सोनू घाट सेबरहज मार्ग का निर्माण भी किया जाएगा। आने वाले समय में अयोध्या के लिए बनने जा रही इनलैंड वॉटर-वे कनेक्टिविटी का एक मुख्य केंद्र बरहज में बनेगा, जिससे किसानों की सब्जियां, फल और मिलेट्स अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पानी के जहाजों से पहुंचाए जा सकेंगे।

गरीब कल्याण योजनाओं का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 6,18,000 गरीबों के लिए नए आवास स्वीकृत हुए हैं। प्रत्येक गरीब को आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड तथा निःशुल्क राशन देना डबल इंजन सरकार की पहचान है। 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के अन्तर्गत रूफ टॉप सोलर प्लांट की व्यवस्था बिजली के बिल को आधे से कम कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बीमारी अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुधार कर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रही है।

अयोध्या धाम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यात्री विश्रामालय का नाम निषादराज व महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, तथा माता शबरी के नाम पर रसोई बन रही है। जन आस्था का सम्मान आवश्यक है और अयोध्या पर आक्षेप स्वीकार्य नहीं है। अयोध्या के विषय में प्रसारित समाचारों की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के पश्चात त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा चुके थे, वे राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बन्द करें। यदि प्रमाण हैं, तो एसआईटी को सौंप दें और राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए। कार्यक्रम को केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास तथा विगत 09 वर्षों में रुद्रपुर और बरहज विधानसभा क्षेत्रों के कायाकल्प की सराहना की।

स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत केंद्र बना गोरखपुर, मुख्यमंत्री ने किया फोर्टिस के सहयोग से निर्मित नए हॉस्पिटल का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 जून, 2026 को बेतियाहाता, जनपद गोरखपुर में फोर्टिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम के सहयोग से नवनिर्मित एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का गरिमामयी शुभारम्भ किया। इस पावन अवसर पर उन्होंने पूर्व मंत्री स्व0 श्री मार्कण्डेय चन्द की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और नवनिर्मित हॉस्पिटल परिसर का गहनता से अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज के समय में आमजन के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में संचालित 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' वर्तमान में समूचे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनकर उभरी है। प्रदेश के प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद नागरिक को गुणवत्तायुक्त व निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें, इस पुनीत उद्देश्य से सरकार हर पात्र व्यक्ति को 05 लाख रुपये का मजबूत स्वास्थ्य बीमा कवर निरंतर उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में राज्य के 12 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस योजना के जरिए उत्कृष्ट व निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि प्रतिवर्ष 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से असहाय व गरीब मरीजों के उपचार के लिए सीधे जारी किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीयता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि आम जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही किसी भी हॉस्पिटल और वहां के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने आमजन को एक स्वस्थ जीवनशैली और अनुशासित दिनचर्या अपनाने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री जी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के रूप में आज गोरखपुर में आधुनिक उपचार केंद्र की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है, जो आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हेल्थ केयर का एक उत्कृष्ट और अग्रणी केंद्र साबित होगा। स्व0 मार्कण्डेय चन्द की पावन स्मृतियों कोजीवंत रखते हुए यह चिकित्सालय स्थानीय नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर अनेक बहुमूल्य जिंदगियां बचाने का एक प्रमुख माध्यम बनेगा। साथ ही, इस बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र के अनेक युवाओं को रोजगार के नए और बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे।

स्व0 मार्कण्डेय चन्द जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और जनसेवा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे जमीन से जुड़े एक अत्यंत लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने शून्य से शिखर तक की अपनी ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा तय की थी। वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संबंधों और गोरक्षपीठ के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे। उनके सुपुत्रों श्री सी0पी0 चन्द व डॉ0 अरुण चन्द ने कड़ी मेहनत से अपने पूज्य पिता की स्मृति में गोरखपुर के हृदयस्थल बेतियाहाता में इस शानदार सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया है। अब स्थानीय कुशल डॉक्टरों की समर्पित टीम और गुरुग्राम के विख्यात फोर्टिस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ मिलकर इस क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के एक बड़े और जनोपयोगी कार्यक्रम को पूरी गति के साथ आगे बढ़ाएंगे।

उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों में हुए ऐतिहासिक एवं सकारात्मक बदलावों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज राज्य में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को पूरी सुरक्षा, सम्मान और शासन की समस्त जनकल्याणकारी सुविधाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के संकल्प के साथ सरकार 'एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज' की नीति पर पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2017 से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और एकमात्र बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज भी स्वयं बदहाली का शिकार था। वर्तमान डबल इंजन सरकार के नीतिगत प्रयासों के फलस्वरूप आज गोरखपुर में न केवल बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, बल्कि यहां एम्स (AIIMS) भी पूरी क्षमता के साथ सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की व्यापक उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि आज गोरखपुर के साथ-साथ महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और चन्दौली जैसे जनपदों में शानदार सरकारी मेडिकल कॉलेज बनकर पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, जबकि बलिया के लिए भी नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन सभी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की बेहतरीन टीमें और विश्वस्तरीय निःशुल्क उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि 'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) के माध्यम से स्थानीय कला को बढ़ावा देने तथा 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना से हर क्षेत्र के अनूठे व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने के अभिनव प्रयासों ने आज उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी दुनिया के नजरिए (परसेप्शन) को पूरी तरह बदल दिया है और यहां के युवाओं को एक नई व गौरवमयी पहचान दिलाई है।

चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ते निजी निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में आईसीयू, डायलिसिस, ब्लड बैंक और प्लेटलेट्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था, जिसके कारण गंभीर मरीजों को विवश होकर दिल्ली, मुम्बई अथवा लखनऊ जैसे महानगरों की ओर दौड़ना पड़ता था। इस दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए वर्ष 2007 में उन्होंने स्वयं गोरखनाथ हॉस्पिटल में सबसे पहले 10 बेड के आईसीयू, पहली ब्लड सेपरेटर मशीन और पहली डायलिसिस मशीन की स्थापना करवाई थी। आज अत्यंत गौरव का विषय है कि सरकार की सकारात्मक एवं निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण गोरखपुर के लगभग प्रत्येक प्रतिष्ठित चिकित्सालय में ये सभी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत सुलभता से मौजूद हैं, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अब अपने घर के समीप ही सर्वोत्तम और त्वरित इलाज मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब मुख्यमंत्री ने किया जेवर में मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 27 जून, 2026 को जनपद गौतमबुद्धनगर के यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के सेक्टर-10 में अम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड एवं कोरिया गणराज्य के एसेन्ट-के सर्किट के ज्वॉइंट वेंचर से स्थापित होने वाले 6,785 करोड़ रुपये लागत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भव्य शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत तीव्र गति से विकसित होकर वैश्विक पटल पर नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सुदृढ़ कानून व्यवस्था, 36 सेक्टोरल पॉलिसीज तथा 75,000 एकड़ के विशाल लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा और सुरक्षित निवेश गंतव्य बनकर उभरा है, जिससे राज्य देश के विकास का मुख्य ग्रोथ इंजन बनकर अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि यह नया प्रोजेक्ट देश को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नया हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में जिन सेमीकंडक्टर्स को भारत दुनिया के अन्य देशों से आयात करता है, इस अत्याधुनिक यूनिट के क्रियाशील होने के बाद उनका निर्माण यहीं उत्तर प्रदेश की धरती पर हो सकेगा और हम इसे दुनिया के अन्य देशों को निर्यात करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कोरिया गणराज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि आक्रामक रणनीति, पूर्ण समर्पण भाव और आत्मानुशासन के बल पर कोई भी देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक गढ़ बन सकता है। राज्य सरकार निवेशकों को 'सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म' के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी पारदर्शिता के साथ सभी आवश्यक इंसेंटिव और अनापत्तियां समयबद्ध ढंग से उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य में नए स्टार्टअप्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार हो रही है।

परियोजना को समय से धरातल पर उतारने में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के अभिनव प्रयासों और अमूल्य सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कानपुर और झांसी के बीच 56 हजार एकड़ क्षेत्रफल में 'बीडा' (BIDA) के रूप में एक नया औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बेहद कम समय में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जेवर क्षेत्र, जो कभी 'जंगलराज' के लिए जाना जाता था, वह वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण अब 'मंगलराज' में बदल चुका है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात के बाद से इस पूरे क्षेत्र में वैश्विक स्तर के बड़े निवेश प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं।

कोरिया गणराज्य के साथ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरियाई इतिहास के अनुसार उनकी पूज्य रानी 'क्वीन हो' वास्तव में पावन अयोध्या धाम की राजकुमारी रत्ना थीं, जो जलमार्ग से कोरिया पहुंची थीं। उनकी पावन स्मृति में अयोध्या में एक भव्य पार्क का निर्माण भी कराया गया है, जिसका शिलान्यास कोरिया की तत्कालीन फर्स्ट लेडी के आगमन पर हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य की 96 लाख एमएसएमई इकाइयों को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना के माध्यम से वैश्विक पहचान मिली है। आज उत्तर प्रदेश देश में मोबाइल फोन निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जिसकी देश के कुल मोबाइल उत्पादन में 55 प्रतिशत की विशाल भागीदारी है। देश के 55 से 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण भी अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किया जा रहा है।

इस गरिमामयी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जेवर अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र बन रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को पूरी तरह बदल देने वाले एक बड़े ऐतिहासिक निर्णय को साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन को स्वीकृति दे दी है, जिसके माध्यम से दिल्ली से लखनऊ की दूरी मात्र 02 घंटे 10 मिनट और जेवर से लखनऊ की दूरी मात्र 1 घंटे 40 मिनट में तय की जा सकेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक व तकनीकी प्रदेश के रूप में हो रहे विकास तथा यहां के सुरक्षित व निवेश-मित्र वातावरण की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

कार्यक्रम के अंत में अम्बर एंटरप्राइजेज के सीईओ श्री जसबीर सिंह और एसेन्ट-के सर्किट के निदेशक व सीईओ श्री योंगहो चो ने उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन द्वारा मिले पूर्ण और बाधा रहित सहयोग के लिए मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून-व्यवस्था और निवेश-अनुकूल नीतियां ही पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट जगत को यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही हैं, जो देश को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को धरातल पर पूरा करेंगी।

जेवर में सौर ऊर्जा क्रांति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ₹8,200 करोड़ के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 27 जून, 2026 को जनपद गौतमबुद्धनगर के यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के सेक्टर-8 में सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 8,200 करोड़ रुपये की लागत वाले 'इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट' का भव्य शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज दुनिया में एक नई उड़ान भरने को तैयार है। भारत ने विश्व की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही विकास का एक बेहतरीन सस्टेनेबल मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट की चर्चा करते हुए कहा कि ऊर्जा की आत्मनिर्भरता ही किसी भी देश की निरंतर प्रगति की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी के विजन का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 06 लाख से अधिक परिवार 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के माध्यम से सौर ऊर्जा अपनाकर अपने बिजली बिलों में 50 से 60 प्रतिशत की बचत कर रहे हैं और राज्य में घरों की छतों से लगभग 2,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा हो रही है।

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को साझा करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य 6,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर रहा है और सरकार का लक्ष्य अगले 02-03 वर्षों में इसे 20 हजार मेगावाट तक पहुँचाने का है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी का एक मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा के साथ-साथ पराली भी है, जिससे कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीआई) और एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार की प्रभावी एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के कारण उत्तर प्रदेश आज देश में सर्वाधिक (लगभग 55 प्रतिशत) एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य बन चुका है, जिसने हमारी शुगर इंडस्ट्री को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया है। विगत 09 वर्षों में राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को 03 लाख 22 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है। सरकार का अगला लक्ष्य प्रदेश में एक वर्ष के भीतर 100 नए सीबीजी प्लांट स्थापित करने का है।

यीडा सेक्टर-8 में सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए जा रहे इस निवेश की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का 'सिंगल विंडो सिस्टम' बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पारदर्शी निवेश की बेहतरीन सुविधा देता है। सुखबीर सिंह जी की अगुवाई में हो रहा यह 8,200 करोड़ रुपये का निवेश देश को सौर सेल विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस प्लांट के माध्यम से प्रतिवर्ष 06 गीगावाट सोलर सेल और 05 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो भारत की एक्सपोर्ट पावर को भी बढ़ाएगा। अब तक जिन सौर तकनीकों के लिए भारत को चीन और अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह तकनीक अब इसी जेवर क्षेत्र में निर्मित होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर हमारे युवाओं, इंजीनियरों और तकनीशियनों को बड़े पैमाने पर रोजगार व ग्रीन इकोनॉमी का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा।

जेवर क्षेत्र के ऐतिहासिक कायाकल्प पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 09 वर्ष पूर्व उपेक्षित रहा यह क्षेत्र, जो कभी अपराध और जंगलराज का गढ़ था, वह वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण अब 'मंगलराज' में तब्दील होकर देश की अर्थव्यवस्था का असली 'जेवर' बन चुका है। जेवर में अब भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ से कॉमर्शियल उड़ानें भी सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी हैं। अब इस क्षेत्र को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट और सोलर सेल विनिर्माण हब के रूप में 200 एकड़ क्षेत्रफल में तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ फिल्म सिटी, अपैरल सिटी, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भी आकार ले रहा है, जो विकास की अनंत संभावनाओं को नई उड़ान देगा।

मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अपने प्रत्येक इन्वेस्टर पार्टनर को पूरा सम्मान, सुरक्षा और प्रोत्साहन देता है। राज्य के पास वर्तमान में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज और 75,000 एकड़ का एक विशाल लैंड बैंक मौजूद है। इसके साथ ही प्रदेश एक्सप्रेस-वे और शानदार रेलवे नेटवर्क से लैस है, जहाँ हर उद्योग को कनेक्टिविटी देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सेल इंडस्ट्रीज समय सीमा के भीतर इस बड़े प्रोजेक्ट को पूर्ण कर विकसित भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

नोएडा में ₹2,479 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य प्रशासनिक भवन का लोकार्पण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 27 जून, 2026 को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर गौतमबुद्धनगर के नोएडा सेक्टर-96 में ₹390 करोड़ की लागत से निर्मित नोएडा प्राधिकरण के भव्य मुख्य प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ₹2,479 करोड़ की लागत वाली 70 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कार्य करने की सुदृढ़ इच्छाशक्ति और स्पष्ट विज़न के बल पर आज उत्तर प्रदेश के प्रति वैश्विक नजरिया (परसेप्शन) पूरी तरह बदल चुका है। विगत 09 वर्षों में राज्य ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में जो नए मानक स्थापित किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज गौतमबुद्धनगर जनपद देश में निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य (बेस्ट डेस्टिनेशन) बनकर उभरा है।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026' के चतुर्थ संस्करण का कर्टेन रेज़र जारी किया। उन्होंने ओडीओपी व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट, एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी के चेक तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जेवर क्षेत्र के किसानों को आबादी भूखंड के आरक्षण पत्र और नोएडा प्राधिकरण के 4,800 संविदा कर्मियों को ₹05 लाख तक के कैशलेस इलाज हेतु चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण के इस नए और आधुनिक भवन के चालू होने से अब किसानों, उद्यमियों और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान एक ही छत के नीचे संभव हो सकेगा। उन्होंने पूरी कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने तथा 'इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री जी ने जेवर क्षेत्र के ऐतिहासिक बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी अपराध और जंगलराज का केंद्र था, आज वह विकासपरक नीतियों के कारण 'मंगलराज' में तब्दील हो चुका है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, और जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होंगी। इस क्षेत्र में ₹7,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लांट और ₹8,200 करोड़ के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी जा चुकी है, जिससे यह क्षेत्र सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल हब बन रहा है। इसके साथ ही यहाँ बन रही फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब युवाओं के लिए रोजगार के अनंत अवसर सृजित कर रहे हैं।

एमएसएमई सेक्टर की मजबूती पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं जिनमें 03 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना आज आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बन चुकी है, जिसके सहयोग से उत्तर प्रदेश का वार्षिक निर्यात ₹02 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। उन्होंने बताया कि भारत के कुल मोबाइल निर्माण में 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। इसी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए आगामी 25 से 29 सितंबर, 2026 तक ग्रेटर नोएडा में भव्य इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा।

मुख्यमंत्री जी ने पारंपरिक खान-पान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन' (एक जनपद एक व्यंजन) योजना की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रांतीय व्यंजनों को वैश्विक मान्यता दिलाना और उन्हें जीआई टैग से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि जो प्रदेश कभी 'बीमारू' माना जाता था, वह विगत 06 वर्षों से लगातार 'रेवेन्यू सरप्लस स्टेट' बना हुआ है और पिछले 09 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ चुकी है।

हाथरस बनेगा नया औद्योगिक और रोजगार का गढ़: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 28 जून, 2026 को जनपद हाथरस के विधानसभा क्षेत्र सिकन्दरा राऊ एवं सादाबाद की ₹548 करोड़ लागत की 143 विकास परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक तबके के जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानती है और सभी जरूरतमंदों को बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चाबियां तथा स्मार्टफोन आदि वितरित किए। इसके पूर्व उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर जनपद में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया तथा महिलाओं की गोदभराई व 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत हरिशंकरी पौधरोपण किया।

मुख्यमंत्री जी ने ब्रज की देहरी के रूप में विख्यात बलदाऊ की पावन धरा हाथरस के पराक्रम और काका हाथरसी के हास्य-व्यंग्य को नमन करते हुए कहा कि सुरक्षा के बेहतर वातावरण में ही विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश दंगों, अराजकता और कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, जहाँ बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। वर्तमान सरकार ने सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से भयमुक्त माहौल बनाया है, जिससे अब सभी पर्व और त्योहार पूरी शांति के साथ संपन्न हो रहे हैं। आज हाथरस अपनी हींग, घी, मक्खन और गुड़ के लिए वैश्विक पहचान रख रहा है। मथुरा-बरेली फोर लेन से जुड़े इस औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से नए उद्यम लग रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ रही हैं।

अन्नदाता किसानों की समृद्धि का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाथरस के आलू उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें वैल्यू एडिशन से जोड़ा जा रहा है। क्षेत्र में प्रोसेसिंग सेंटर और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सुदृढ़ होने से उद्यमियों द्वारा सीधे खेतों से आलू खरीदा जाएगा, जिससे किसानों का कोल्ड स्टोरेज का खर्च बचेगा। किसानों को सही समय पर उत्तम बीज उपलब्ध कराने के लिए आगरा में 'अंतरराष्ट्रीय पोटैटो सेंटर' का क्षेत्रीय केंद्र स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर हाथरस की सड़कों, पुलों, फ्लाई ओवर, नए मेडिकल कॉलेज और सिकन्दरा राऊ के बस स्टैंड के विकास के लिए भूमि आवंटन तथा धनराशि स्वीकृति की प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कौशल विकास पर बल देते हुए बताया कि हाथरस में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर 'एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' विकसित किया जा रहा है, जिससे हाथरस, कासगंज और एटा के युवाओं को स्किलिंग के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत युवाओं को ₹05 लाख तक का गारंटी व ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकारें आती हैं, तो विकास के साथ-साथ जन आस्था का भी सम्मान होता है। हाथरस में 22 से अधिक मंदिरों का सुंदरीकरण कराया गया है और सरकार अयोध्या, काशी व मथुरा के उत्थान तथा उनकी पौराणिक पहचान बनाए रखने के लिए लगातार बुनियादी सुविधाएं बढ़ा रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज कर दिया है और 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र पर चलते हुए सभी 75 जनपदों की 350 तहसीलों का समग्र विकास कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करना ही डबल इंजन सरकार का मुख्य ध्येय है, जिसके तहत समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक निःशुल्क राशन, आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाई जा रही हैं।

पीलीभीत में सौर ऊर्जा, इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईको-टूरिज्म को मिली रफ़्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 29 जून, 2026 को जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा एवं बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में ₹569 करोड़ से अधिक लागत की 66 विकास परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीलीभीत अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव-विविधता और विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए विख्यात है। यहाँ के हुनरमंद कारीगरों ने कृष्ण-कन्हैया की बाँसुरी को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डबल इंजन सरकार के निरंतर सहयोग और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से जनपद पीलीभीत आने वाले समय में विकास की प्रक्रिया के साथ ईको-टूरिज्म के एक नए वैश्विक हब के रूप में स्थापित होगा।

इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विस्थापित बंगाली परिवारों को भूमि संबंधी अधिकार पत्र (पट्टे) तथा भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 05 दशक से भी अधिक समय पूर्व तत्कालीन सरकारों की तुष्टिकरण की नीति और सत्ता लोलुपता के कारण विभाजन की त्रासदी झेलकर बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप सम्मानपूर्वक पुनर्वासित कर नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रथम चरण में पीलीभीत के लगभग 2,500 बंगाली परिवारों यानी 15,000 लोगों को इस कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ मिला है, जिससे अब वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकेंगे। लखीमपुर खीरी और बिजनौर के बाद अब रामपुर में भी इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज जिन विस्थापितों को आवासीय पट्टे और नागरिकता प्रदान की गई है, उनमें अधिकांश दलित, वंचित और अति पिछड़ी जाति से संबंधित हैं, जिनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी सुध नहीं ली थी। पूर्व की सरकारों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण न होकर केवल उनका अपना परिवार था, जिसके कारण पीलीभीत मेडिकल कॉलेज, सुदृढ़ पुलों और यहाँ के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता मिलने में दशकों का विलंब हुआ। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उन्होंने गौरवपूर्वक कहा कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से 'नो दंगा, नो कर्फ्यू' की स्थिति है, और राज्य दंगामुक्त व माफियामुक्त होकर व्यापारियों, बेटियों, युवाओं और किसानों की सुरक्षा व खुशहाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जनपद के ढांचागत और आर्थिक विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब जागरूक जनता सही और योग्य जनप्रतिनिधि चुनती है, तो क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, आधुनिक सड़कें और विकास योजनाएं आती हैं। वर्तमान में यहाँ के युवा 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान', 'पीएम विश्वकर्मा योजना' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के माध्यम से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का बड़ा हब बन रहा है, जहाँ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें निर्मित हो रही हैं। इसी क्रम में गोरखपुर से पीलीभीत होते हुए मुरादाबाद, शामली और पानीपत तक जाने वाला एक विशाल इकोनॉमिक कॉरिडोर पीलीभीत से गुजर रहा है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी और व्यापार की गति को कई गुना बढ़ा देगा।

मुख्यमंत्री जी ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रगति का वास्तविक आधार गति है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित देश के सबसे लंबे 'गंगा एक्सप्रेस-वे' के चालू होने से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ से लखनऊ तथा प्रयागराज की दूरी आधी रह गई है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कार्य करते हुए न केवल अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित कर रही है, बल्कि प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत को भी पूरा सम्मान प्रदान कर रही है।

पीतल नगरी में प्रगति की नई गूंज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को दी ₹365.50 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 29 जून, 2026 को जनपद मुरादाबाद में आयोजित दानवीर भामाशाह जयंती एवं व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम में मुरादाबाद सदर, मुरादाबाद देहात व कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की ₹365.50 करोड़ लागत की 63 विकास परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जीएसटी भुगतान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अग्रणी व्यापारियों को प्रतिष्ठित भामाशाह सम्मान से नवाजा। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, आवंटन पत्र, प्रतीकात्मक चेक, चाबियां तथा आयुष्मान कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक 'बदलता मुरादाबाद' पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके उपरांत, उन्होंने निर्माणाधीन गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया और परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

दानवीर भामाशाह जी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करने वाले भामाशाह का व्यक्तित्व राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए एक बड़ी घोषणा की कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, डबल इंजन सरकार उसे ₹10 लाख का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यापारियों का सामर्थ्य ही प्रदेश की प्रगति का असली आधार है। 09 वर्ष पहले का मुरादाबाद जहाँ दंगों, कर्फ्यू, अराजकता और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, वहीं आज का मुरादाबाद अपनी पीतल नगरी की वैश्विक पहचान, चौड़ी सड़कों, स्मार्ट सिटी और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है, जो अब एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो चुका है।

मुरादाबाद की गौरवशाली विरासत को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के महान सेनानी और मुरादाबाद की विभूति स्व. दाऊ दयाल खन्ना जी की स्मृति में मुरादाबाद के लाइनपार क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर 'दाऊ दयाल खन्ना नगर' किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने गुरु जम्भेश्वर मंदिर में एक भव्य कॉरिडोर विकसित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से निर्मित श्रीराम वाटिका, भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा, हनुमान वाटिका और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के कृतित्व के अनुरूप बनाई गई 'संविधान वाटिका' की भूरि-भूरि प्रशंसा की, जो वर्तमान पीढ़ी को हमारी महान लोकतांत्रिक व पौराणिक विरासत से जोड़ने का कार्य कर रही है।

प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 09 वर्षों में रिकॉर्ड 09 लाख युवाओं को पारदर्शी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करते हुए राज्य में आज 96 लाख से अधिक इकाइयां संचालित हैं, जिनसे सवा तीन करोड़ नौजवानों को आजीविका मिली है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण आज उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब वाला अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहाँ मुरादाबाद से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ अब गंगा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से प्रयागराज तक की यात्रा भी अत्यंत सुगम और शानदार होने जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की तुष्टिकरण की सोच के कारण विकास पूरी तरह ठप था और केवल दंगे होते थे, परंतु वर्तमान सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाकर बेटियों, व्यापारियों और किसानों को पूर्ण सुरक्षा दी है। आज उत्तर प्रदेश 'बीमारू' राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर लगातार 'रेवेन्यू सरप्लस स्टेट' बना हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य ग्रोथ इंजन के रूप में देश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर किया जा रहा यह चहुंमुखी विकास उत्तर प्रदेश को प्रगति के एक नए और स्वर्णिम मॉडल के रूप में स्थापित करेगा।

स्मार्ट और स्वच्छ बरेली की ओर मजबूत कदम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 30 जून, 2026 को बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा क्रय किए गए 60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन नाथ नगरी बरेली की साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं प्रभावी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर का निर्माण समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है। इन अत्याधुनिक वाहनों के संचालन से न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, बल्कि कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण और सीवर सफाई जैसे जटिल कार्यों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

इन अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों के बेड़े में 06 रोबोटिक मैनहोल सीवर क्लीनिंग मशीनें, 02 स्किड लोडर, 50 सीएनजी ऑटो टिपर तथा 02 बैक-हो लोडर मुख्य रूप से शामिल हैं। इन आधुनिकतम मशीनों के उपयोग से सफाई कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आएगी, जिससे सीवर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिक सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि बेड़े में शामिल की गई रोबोटिक मैनहोल सीवर क्लीनिंग मशीन वास्तव में 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'मेक इन इंडिया' के तहत निर्मित भारत का पहला रोबोटिक स्कैवेंजर 'बैंडीकूट मोबिलिटी' है, जो मैनहोल के भीतर इंसानों के प्रवेश की आवश्यकता को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। यह आधुनिक रोबोट मैनहोल के अंदर जाकर 360 डिग्री तक पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करता है।

तकनीकी विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि बेड़े में शामिल किए गए स्किड लोडर का उपयोग नालों की गाद (सिल्ट) की Micro-Level पर सफाई करने के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार, 'हर दिन चार बिन्स' के अभिनव सिद्धांत के तहत 50 नए सीएनजी ऑटो टिपर्स को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य में लगाया गया है। ये वाहन प्रतिदिन घरों से निकलने वाले कचरे को 04 अलग-अलग श्रेणियों—गीला (हरा), सूखा (नीला), स्पेशल केयर वेस्ट (काला) एवं सैनिटरी वेस्ट (लाल) में संकलित करेंगे। यह महत्वपूर्ण पहल पूरी तरह से मानव श्रम पर निर्भरता को कम करने और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है, जो बरेली को प्रदेश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करेगी।

सहारनपुर में ₹613 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून कॉरिडोर से आर्थिक प्रगति को मिलेगी नई उड़ान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 01 जुलाई, 2026 को जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर एवं सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्रों को 613 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 10 बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 32 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 07 परियोजनाओं का लोकार्पण और 581 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 03 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाबियां, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और टूलकिट प्रदान किए, साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों तथा राजस्व विभाग के रोवर का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में सहारनपुर के विकास कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 01 जुलाई से 15 अगस्त, 2026 तक चलने वाले धारा - 24 के अन्तर्गत 'रोवर द्वारा पैमाइश अभियान' का ऐतिहासिक शुभारम्भ किया। उत्तर प्रदेश सरकार की यह अभिनव पहल पारंपरिक विधियों की तुलना में बेहद कम समय में आधुनिक राजस्व अभिलेखों के अनुरूप सटीक पैमाइश सुनिश्चित करेगी, जिससे मानवीय त्रुटियों, सीमा विवादों और अनावश्यक अदालती मुकदमों में भारी कमी आएगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा परिषद के 'स्कूल चलो अभियान' के दूसरे चरण की भी शुरुआत की और छोटे बच्चों को स्कूल बैग वितरित कर नए भारत की उड़ान के लिए उन्हें सक्षम बनाया।

सहारनपुर को माँ शाकुम्भरी तथा माँ त्रिपुर बाला सुन्दरी की पावन धरा बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश ने विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर काम कर रही है, जिसके तहत बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद को निःशुल्क राशन, रसोई गैस कनेक्शन, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर, पेंशन, आवास और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 12 हजार करोड़ रुपये की लागत वाला दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब सहारनपुर से दिल्ली की दूरी को मात्र डेढ़ घंटे में समेट चुका है, जो न केवल कनेक्टिविटी बेहतर कर रहा है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान दे रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि सड़क और रेलवे के बाद अब सहारनपुर हवाई मार्ग से भी जुड़ने जा रहा है और सरसांवा में सिविल टर्मिनल का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके अलावा, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के दूसरे चरण शुद्ध पेयजल और एसटीपी (STP) परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। स्थानीय हुनर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के माध्यम से यहाँ की प्रसिद्ध वुड कार्विंग (लकड़ी की नक्काशी) को वैश्विक पहचान मिली है और आज यहाँ से 600 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, जिससे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है।

क्षेत्र की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर बात करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब सहारनपुर दंगों से पूरी तरह मुक्त है। माँ शाकुम्भरी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहाँ एक एलिवेटेड कॉरिडोर व फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी मौसम में यातायात बाधित न हो। पूर्ववर्ती सरकारों पर विजन की कमी और स्वार्थी दृष्टिकोण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान डबल इंजन सरकार राज्य के सभी 1 लाख 7 हजार गांवों, 57 हजार ग्राम पंचायतों और 762 नगर निकायों का समान रूप से विकास कर रही है। आज दिव्य-भव्य अयोध्या और पावन काशी में महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जैसे महापुरुषों की विरासत का पूरा सम्मान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से राज्यव्यापी 'स्कूल चलो अभियान' का शुभारम्भ किया, बच्चों को बांटी पाठ्य-सामग्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 01 जुलाई, 2026 को जनपद सहारनपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्माईलपुर (कम्पोजिट) से राज्यव्यापी 'स्कूल चलो अभियान-2026' के द्वितीय चरण का गौरवमयी शुभारम्भ किया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को नवीन शैक्षणिक सत्र की पाठ्य-पुस्तकें, स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की, साथ ही जनपद के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को स्वयं अपने हाथों से मिड-डे-मील परोसा, नन्हें बच्चों का अन्नप्राशन भी किया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के नवनिर्माण की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुए इस अभियान के अत्यंत उत्साहजनक और ऐतिहासिक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की साफ नीयत, शिक्षा के उन्नयन की स्पष्ट नीति और बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के संकल्प का ही नतीजा है कि आज परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदल चुकी है। वर्ष 2017 से पहले जहाँ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली, पेयजल और फर्नीचर का घोर अभाव था, वहीं राज्य सरकार द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्यमियों के सहयोग से 96 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि जब बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें, जूते-मोजे और स्वेटर सीधे मिलने शुरू हुए, तो परिषदीय विद्यालयों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा। इसी का परिणाम है कि विगत 9 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 60 लाख से अधिक नए बच्चों का नामांकन हुआ है और स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 19-20 प्रतिशत से भारी गिरावट के साथ मात्र 03-04 प्रतिशत पर आ गया है।

उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा ही समाज को योग्य चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता और कर्तव्यशील नागरिक देती है, इसलिए कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे क्योंकि एक भी बच्चे का अशिक्षित रहना पूरे राष्ट्र की क्षति है। मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को एक बड़ा जन-आन्दोलन बनाने की अपील करते हुए समाज के हर वर्ग से अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी (ICT) लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए 1.5 लाख से अधिक सहायक उपकरण बांटे गए हैं और एस्कॉर्ट एलाउन्स व स्टाइपेण्ड के रूप में सीधे आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 'लर्निंग बाई डूइंग' (करके सीखना) के माध्यम से बच्चों के हुनर को निखारा जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चे आज पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।

शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये तथा अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके साथ ही, सरकार जल्द ही प्रत्येक शिक्षामित्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, अनुदेशक और रसोइया के लिए 5 लाख रुपये की वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू करने जा रही है। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे स्कूलों में बच्चों को प्यार, कविताओं और गानों के माध्यम से बेहतरीन व रुचिपूर्ण माहौल में शिक्षा दें, जिससे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिले।

रामपुर में नए चैप्टर की हुई शुरुआत : मुख्यमंत्री ने किया ₹690 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 30 जून, 2026 को जनपद रामपुर के मिलक एवं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्रों को ₹690 करोड़ से अधिक की लागत वाली 102 ऐतिहासिक विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। एक भव्य समारोह में इन जनोपयोगी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड परीक्षा-2026 के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार व 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के लाभार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। साथ ही, सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यापारियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व स्वीकृति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम से पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन भी किया।

रामपुर को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले और बाद के रामपुर में आया बदलाव सबके सामने प्रत्यक्ष है। पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण जहाँ यहाँ का पारंपरिक उद्यम ठप था, वहीं वर्तमान डबल इंजन सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के माध्यम से रामपुर के पैच वर्क, जरी वर्क और वॉयलिन निर्माण को वैश्विक पहचान दी है। उन्होंने रेखांकित किया कि आज रामपुर का प्रसिद्ध चाकू जनता की सुरक्षा का पर्याय बनकर विकास का माहौल तैयार कर रहा है। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करते हुए सड़कों को 4-लेन में बदला जा रहा है और यहाँ से गुजरने वाला गोरखपुर-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर क्षेत्र की प्रगति को नई गति देगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर की रुद्र बिलास चीनी मिल के पुनरुद्धार और विस्तारीकरण के लिए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जल्द धनराशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले की अन्यायी सरकारों में गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जे होते थे, लेकिन आज राज्य में कानून का राज है। वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 75 जनपदों, 350 तहसीलों और 825 विकास खंडों का समान रूप से विकास कर रही है और हर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 'बीमारू राज्य' की श्रेणी से बाहर आकर देश की 'टॉप थ्री' अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। आज प्रदेश में त्योहार पूरी भव्यता और शांति के साथ मनाए जाते हैं तथा कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलती है। सरकार तुष्टिकरण की जगह आमजन के 'संतुष्टिकरण' पर काम कर रही है।

जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पारदर्शी ई-पॉस व्यवस्था से अब हर गरीब को हर महीने शत-प्रतिशत मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रत्येक जरूरतमंद को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर और उज्ज्वला योजना से रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है। युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए भर्तियों को पारदर्शी बनाकर रामपुर के युवाओं को भी बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के 96 लाख एमएसएमई (MSME) उद्यमियों को ₹5 लाख का सुरक्षा बीमा कवर दिया गया है तथा हर तहसील में फायर स्टेशन व शिक्षण संस्थानों की स्थापना तेजी से की जा रही है। सुशासन और विकास की इस तेज रफ्तार ने रामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर दिया है।